भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3537

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य

3537. श्री सौमेंदु अधिकारी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत कुछ वर्षों में राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रस्तावित राशि के संदर्भ में और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में सरकार के राजकोषीय घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए और ऋण-जीडीपी अनुपात को वर्तमान 56.1 प्रतिशत से घटाकर 2031 तक 50±1 तक पहुंचाने के लिए राजकोषीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% से घटकर वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% (अनंतिम) हो गया है। विगत पांच वर्षों के दौरान राशि और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे (एफडी) का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वित्त वर्ष (एफवाई)	राजकोषीय घाटा (₹ करोड़ में)	जीडीपी के % के रूप में एफडी
2021-22	15,84,521	6.7
2022-23	17,37,755	6.7
2023-24	16,54,643	5.7
2024-25	15,74,431	4.9
2025-26 (अनंतिम)	15,19,169	4.4

नोट: वित्त वर्ष 2022-23 के बाद के लिए जीडीपी नई श्रृंखला (आधार वर्ष 2022-23) पर आधारित है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, जीडीपी की पुरानी श्रृंखला (आधार वर्ष 2011-12) को प्रतिशत पर लाने के लिए लिया जाता है।

बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा 16,95,768 करोड़ रुपये (जीडीपी का 4.3 प्रतिशत) रहने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) संभावित विकास प्रवृत्तियों और आकस्मिक विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पिछले बजटों में घोषित राजकोषीय घाटे और ऋण समेकन उपायों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी पूंजीगत व्यय पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है। उदाहरण के लिए, बजट अनुमान 2026-27 में सरकार के ऋणों (₹16.96 लाख करोड़) का उपयोग 17.15 लाख करोड़ रुपये के प्रभावी पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

*****